

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3557

जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

यूपीआई-फवारा एकीकरण योजना

†3557. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत और मालदीव के बीच हुए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) - फवारा एकीकरण योजना का ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
- (ख) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके पूरी तरह से शुरू होने की प्रत्याशित समय-सीमा क्या है; और
- (ग) क्या इस योजना से मालदीव में काम कर रहे भारतीय नागरिक अपना वेतन भारत भेज सकेंगे और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह जानकारी दी है कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) को मालदीव की तीव्र भुगतान प्रणाली, 'फवारा' के साथ एकीकृत करने के लिए जुलाई 2025 में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इस प्रकार का एकीकरण दोनों देशों के बीच वास्तविक समय सीमा-पार व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) प्रेषण को सुविधाजनक बनाता है। इसके अलावा, यह लाभार्थियों के खातों में तुरंत क्रेडिट, 24x7 उपलब्धता और वास्तविक समय में प्राप्तकर्ता के सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा मालदीव से भारत भेजे जाने वाले प्रेषण के लिए 30 जुलाई 2026 को शुरू हो गई थी और यह मालदीव में काम करने वाले भारतीय नागरिकों को लागू लेनदेन सीमाओं और विनियमों के अधीन भारत में पैसे ट्रांसफर करने में सक्षम बनाती है।
